



KHETI DUNIYAN

खेती दुनिया

Kheti Duniyan, Patiala

All Subject to Patiala Jurisdiction.

भारत का एक सुप्रसिद्ध हिन्दी
कृषि समाचार-पत्र (न्यूज़ पेपर)

www.khetiduniyan.in

• Issue Dated 14-09-2024 • Vol.8 No.37 • H.O. : KD Complex, Gaushala Road, Patiala-147001 (Pb.) Ph. : 0175-2214575 • Page : 12 E-mail : khetiduniyan1983@gmail.com

किसान मेला विशेषांक

BOOK POST - PRINTED MATTER

Godrej agrovet
brighter farming

CROP PROTECTION BUSINESS



धान के लिए संपूर्ण समाधान

पाए सुरक्षा और उच्च गुणवत्ता की पैदावार

Godrej agrovet
brighter farming

फूड प्रोसैसिंग में किसानों व एस.एम.ईज़ का ग्लोबल कम्पनियों से गठजोड़ हो

खेत से खाने की थाली तक पहुंचने से पहले ही करीब 90,000 करोड़ रुपए की फसलें रख-रखाव के अभाव में सालभर में बर्बाद हो जाती है। इसे कम करने के लिए खेतों के निकट फूड प्रोसैसिंग इकाईयों को कोल्ड सल्लाई चेन से जोड़ने व भारतीय कम्पनियों के ग्लोबल कम्पनियों के साथ गठजोड़ से किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज़ मंत्रालय 19 से 22 सितम्बर को दिल्ली में 'वर्ल्ड फूड इंडिया' की मेजबानी करेगा।

केन्द्रीय बजट में भी 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जलवायु संकट से निपटने, कृषि उत्पादन में वृद्धि व प्रोसैस्ड फूड का

में संतुलन साधने और महंगाई पर लगाम के नाम पर एक्सपोर्ट रोक दिया जाता है।

बीते एक दशक से देश से कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में प्रोसैस्ड फूड का हिस्सा केवल 25 प्रतिशत रहा है। टैक्नोलॉजी आधारित बढ़ी उत्पादन क्षमता से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करके ही ग्लोबल बाज़ार में प्रोसैस्ड फूड का कारोबार बढ़ाया जा सकता है।

स्विट्जरलैंड की नैस्ले जैसी फूड प्रोसैसिंग व पेय पदार्थ निर्माता कम्पनी ने टैक्नोलॉजी व रिसर्च की मदद से सालाना 111 बिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार स्थापित किया है, जबकि 9 बिलियन डॉलर के कारोबार से भारत की अमूल

देश भी प्रोसैस्ड कृषि उत्पादों के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं।

एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू किए जाने के 5 वर्षों के बाद भी भारत का प्रोसैस्ड फूड एक्सपोर्ट

नुकसान का अनुमान लगाया है। इससे उभारने के लिए खेतों के निकट फसलों की छंटाई व ग्रेडिंग के अलावा

वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक 10,900 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंकड इंसैटिव (पी.एल.आई.) स्कीम का लक्ष्य बड़ी ग्लोबल कम्पनियों को भारत से उत्पादन व एक्सपोर्ट के लिए आकर्षित करना है। मई 2024 तक उत्पादन प्रोत्साहन योजना के 90 प्रतिशत फंड का उपयोग नहीं हो पाया है। केवल 158 छोटे व मध्यम उद्यमियों (एस.एम.ईज़) लाभार्थियों को 1073 करोड़ रुपए



डॉ. अमृत सागर मित्तल,
वाइस चेयरमैन सोनालीका



में मात्र 6.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी से 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कारोबार हुआ है। प्रोसैस्ड फूड के ग्लोबल बाज़ार में भले ही भारत की रैकिंग 21वें से 17वें नंबर पर आ गई है, परन्तु फसलों की बर्बादी कम करने के लिए प्रोसैसिंग बढ़ाने की जरूरत है।

90 हजार करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद

हाल ही में जारी 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक चीन के बाद भारत सालाना औसत 300 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल व सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद यहां केवल 2.7 प्रतिशत सब्जियों की व 4.5 प्रतिशत फलों की प्रोसैसिंग होती है। जबकि दूध 21.1 प्रतिशत, मांस 34.2 प्रतिशत व 15.4 प्रतिशत मछली की प्रोसैसिंग के मुकाबले चीन में 25.30 प्रतिशत व पश्चिमी देशों में 60.80 प्रतिशत प्रोसैसिंग होती है।

हाइटेक प्रोसैसिंग क्षमता की कमी के कारण हमारी फसलें बर्बाद हो रही है। कटाई के बाद करीब 18 से 25 प्रतिशत फसलों का नुकसान होता है, जबकि करीब 45 प्रतिशत फल व सब्जियां खाने की प्लेट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो रही हैं। नीति आयोग ने सालाना करीब 90,000 करोड़ रुपए की फसलों के

प्रोसैसिंग क्षमता बढ़ाने का सुझाव आयोग ने दिया है।

किसान प्रोत्साहित किए जाएं

खेतों में फसलों की बर्बादी घटाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। 2020 में केन्द्र सरकार ने खेतों के निकट कोल्ड स्टोरेज चेन व कटाई के बाद फसलों के रख-रखाव के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक ट्रिलियन रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से किसानों व उद्यमियों को आसान कर्ज का प्रावधान किया गया।

हाल ही में जारी फूड प्रोसैसिंग पॉलिसी में तामिलनाडु ने फसलों की बर्बादी कम करने व कृषि उपज मूल्य बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। यह पॉलिसी किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) और फूड प्रोसैसिंग उद्योगों को केन्द्रीय योजनाओं से वित्ती सहायता पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। फूड प्रोसैसिंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्य ने भी 'एग्रीबिज़नैस एंड फूड प्रोसैसिंग पॉलिसी' लागू की है, जबकि पंजाब में ऐसी पहल का किसानों को इंतजार है।

पी.एल.आई. स्कीम में सुधार हो

फूड प्रोसैसिंग उद्योग के लिए

जारी हो पाए, जबकि स्कीम की समय सीमा आवी से भी अधिक बीत चुकी है।

स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नीतिगत दखल की जरूरत है। पी.एल.आई. स्कीम की मदद से ग्लोबल बाज़ार में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारे एस.एम.ईज़ का हाइटेक 'ग्लोबल एंकर' कम्पनियों के साथ सरकार को गठजोड़ स्थापित करवाना होगा। फूड प्रोसैसिंग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति के बावजूद बीते एक दशक के दौरान भारत में 500 अरब रुपए की एफ.डी.आई. आई, जिसे अधिक बढ़ाने की जरूरत है।

आगे की राह

फूड प्रोसैसिंग सैक्टर खेती में बड़ा बदलाव ला सकता है। ग्लोबल कम्पनियों की अत्याधुनिक फूड प्रोसैसिंग टैक्नोलॉजी की मदद से अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुंच बढ़ाई जा सकती है। ग्लोबल कम्पनियों की किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) और एम.एम.ईज़ के साथ साझेदारी करवाने के लिए केन्द्रीय फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज़ मंत्रालय कारगर पहल करे।



एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया गया है। बीते एक साल में कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में 8 प्रतिशत की गिरावट ने खेतों व संबंधित कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 2022-23 में 53.2 बिलियन डॉलर कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट 2023-24 में 48.9 बिलियन डॉलर रहा। 2014 से 2023 के दौरान एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की औसत वार्षिक बढ़ोत्तरी केवल 2 प्रतिशत रही।

मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मांस, मसाले, चीनी, चाय व कॉफी का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, इसमें भी कई बार घरेलू मांग व सल्लाई

फूड प्रोसैसिंग में 17वें नंबर पर

प्रोसैस्ड कृषि उत्पादों के सालाना करीब 1 ट्रिलियन डॉलर के ग्लोबल एक्सपोर्ट कारोबार में जर्मनी (63 बिलियन डॉलर) नंबर एक पर है। अमरीका (58 बिलियन डॉलर), नीदरलैंड्स (57 बिलियन डॉलर), चीन (53 बिलियन डॉलर) और फ्रांस का प्रोसैस्ड फूड कारोबार 50 बिलियन डॉलर का है। दक्षिण-इंडोनेशिया, मलेशिया व थाईलैंड जैसे पूर्वी एशियाई

आप बागवानी की शौकीन हैं और सेहत के लिए जागरूक भी, तो घर पर सब्जियां भी उगाइए। बगिया में प्राकृतिक रंग दिखेंगे और खाने में स्वाद व स्वास्थ्य भी बढ़ेगा।

बाजार में मौजूद अधिकांश सब्जियां स्वादहीन होती हैं, क्योंकि उनमें कीटनाशक दवाओं आदि का छिड़काव किया जाता है। इसलिए घर पर ही बिना कीटनाशक के आसानी से सब्जियां उगाने की विधि हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो न सिर्फ ताजी और पोषक तत्वों से भरपूर होंगी, बल्कि खाने में बहुत स्वादिष्ठ भी लगेंगी।

इन सब्जियों को लगाएं

टमाटर : गमलों में चेरी टमाटर और सन गोल्ड टमाटर आसानी से लग जाते हैं। टमाटर के पौधों को 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है, इसलिए इन्हें छाया में ना लगाएं। पौधे लगाने के 60-70 दिन में ही फल लगने लगते हैं, इसलिए बांस की

डंडियों का सहारा देकर ताकि फलों के बज़न से बैगन : गमले में

छोटे हरे बैगन, इंडियन बैगन, गुलाबी गोल बैगन लगा सकते हैं। चूंकि इन्हें पर्याप्त प्रकाश की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें धूप में रखें। मिट्टी में नमी बनी रहे, इसका भी ध्यान रखें।

लेट्यूस : इसे सलाद पत्ता भी कहते हैं। लेट्यूस लोलो, रेड रोज लेट्यूस, लेट्यूस ओक को गमलों में लगाया जा सकता है। इन्हें छाया में रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी दें क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता

मिर्च : स्वीट पेपर और चिली हॉट

पेपर किस्म को गमले में लगाना उत्तम है। जैविक खाद के चलते ये मिर्च बाज़ार की मिर्च की तुलना में अधिक तीखी और स्वादिष्ठ होती है। गमलों को धूप में रखें ताकि पौधों की पर्याप्त धूप मिले।

पालक : सेवाँ पालक और बेबी पालक को घर पर आसानी से लगाया जा सकता है। इन्हें किसी जड़ उथली हुई रहती है। बेहतर बढ़वार की

लिए इन्हें हल्की छाया में रखें। चाहें तो ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं।

धनिया : खेती धनिया के सूखे बीजों को दो भागों में तोड़ कर गमले की नम मिट्टी में डाल दें। फिर गमले को ऐसी जगह रखें, जहां उसे 4-6 घंटे की पर्याप्त धूप मिले।

इस तरह बनाएं जैविक खाद

दो-दो मुट्ठी ग



Years of
Cultivating
Prosperity

पत्ता लपेटक सुरिडयों के मौत का फरमान



कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

1115, हेमकुन्ट टॉवर, 98 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

खेती दुनिया

KHETI DUNIYAN

मुख्य कार्यालय

के.डी. कॉम्प्लैक्स, गऊशाला रोड, नजदीक शेरे पंजाब मार्केट, पटियाला - 147001 (पंजाब)

फोन : 0175—2214575

मो. 90410—14575

E-mail : khetiduniyan1983@gmail.com

वर्ष : 08 अंक : 37
तिथि : 14-09-2024

सम्पादक

जगप्रीत सिंह

मुख्य शाखाएं

पटियाला

फोन : 0175—2214575
मो. 90410—14575

मुम्बई

दिल्ली

लुधियाना

बाणिठड़ा

सम्पादकीय बोर्ड

डॉ. डी.डी. नारंग
डॉ. जे.एस. डाल
डॉ. आर.एम. फुलझोले

कम्पोजिंग

एकता कम्प्यूटरज़े पटियाला

सर्पदंश का संकट

तुरंत उपचार और सावधानी में ही बचाव



बरसात के इन दिनों में धान आदि की खेती का मौसम होता है, और यही समय सर्पदंश के लिए सबसे अधिक जोखिमपूर्ण होता है। सांप के काटने की घटनाएं अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, जिससे स्त्री-पुरुष किसान, कृषि श्रमिक, और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। सर्पदंश के परिणामस्वरूप कुछ ही समय में मौत, लकवा, सांस लेने में कठिनाई, रक्तस्राव संबंधी विकार, किडनी फेल्पोर, स्थायी विकलांगता, और अंग विच्छेदन हो सकते हैं। यह समस्या विकासशील देशों, विशेषकर कृषि प्रधान ग्रामीण और बन बस्तियों में देखी जाती है। ये घटनाएं स्वास्थ्य संकट नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी डालती हैं। हालांकि, इस समस्या को मानव-वन्यजीव संघर्ष की अन्य घटनाओं की तरह गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इसलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे

सर्पदंश के शिकार लोगों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अस्पतालों में रिपोर्ट करता है, जिससे सर्पदंश की वास्तविक संख्या दर्ज नहीं हो पाती। केंद्रीय स्वास्थ्य जांच ब्यूरो की रिपोर्ट (2016-2020) के अनुसार, भारत में सर्पदंश के मामलों की औसत वार्षिक आवृत्ति लगभग 3 लाख है और लगभग 2,000 मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतों की सटीक



उष्णाकटिबंधीय और उपोष्णाकटिबंधीय क्षेत्रों की उपेक्षित स्वास्थ्य समस्या के रूप में वर्गीकृत किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल दुनिया भर में लगभग 50.4 लाख लोग सांपों द्वारा काटे जाते हैं, और 81,410 से 1,37,880 लोग सर्पदंश से मृत्यु का शिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त, लाखों लोग विकलांगता और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि, सर्पदंश पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और नेशनल

संख्या उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों और बन बस्तियों में होती हैं, जहां पुलिस और अस्पतालों तक मामले नहीं पहुंचते और रिपोर्टिंग नहीं हो पाती।

भारत में मानसून का मौसम, जो आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है, सर्पदंश के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है। इस मौसम में बढ़ और पानी के कारण सांपों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे वे भोजन और आश्रय की तलाश में मानव बस्तियों की ओर आ

जाते हैं। मानसून के दौरान कृषि गतिविधियां भी चरम पर होती हैं, और किसान व मजदूर अनजाने में सांपों के संपर्क में आ सकते हैं, जो उन्हीं घास या मलबे के नीचे छिपे होते हैं। गर्म और गीली परिस्थितियों में शिकार की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे सांपों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं।

जनसंख्या वृद्धि और मानव-जीव संघर्ष के कारण भारत में सांपों और मनुष्यों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। मानव आवास विस्तार प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण करता है, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सांपों के काटने की संभावना बढ़ जाती है।

जलवायु परिवर्तन सांपों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। वनों की कटाई और कृषि विस्तार के कारण सांप भोजन और आश्रय की तलाश में मानव बस्तियों की ओर खिंचे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सहायता और एंटीवेनम की कमी मृत्यु दर को बढ़ाती है।

भारत सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगता की संख्या को आधा करना है। हालांकि, इस समस्या का असली समाधान सावधानी और प्रकृति

जयसिंह रावत

बरौनियां कलां का युवा बना मिसाल

पिता का धंधा संभाला, आज देश में 6 तरह के शहद की सप्लाई

सूजरमुखी, सरसों समेत कई किस्म का शहद



पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिलने का रोना रोने वाले लोगों के लिए बरौनियां कलां गंव का 27 वर्ष का अभिषेक शर्मा के लिए मिसाल है। उसके पिता 3 एकड़ में खेती करते हैं और उसने ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी करने की बजाय अपने पिता के शुरू किए सहायक धंधे (शहद उत्पादन) के कारोबार को अपनाना ज्यादा मुनासिब समझा। शहद के सिफ 5 बॉक्स (डिब्बे) के उत्पादन को आज उसने 1500 बॉक्स तक पहुंचा दिया। अभिषेक के मुताबिक, वह 6 तरह का शहद (जयवाइन, मल्टी, सफेद, सूरजमुखी, सरसों) बनाते हैं। श्रीगंगानगर और श्रीनगर

तैयार माल को बेचने की मार्केटिंग भी सोशल मीडिया पर ही करनी शुरू कर दी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब उनका शहद पंजाब, हरियाणा की सीमाएं लांघ कर देश के लगभग सभी राज्यों में ऑनलाइन सप्लाई किया जा रहा है। सोशल मीडिया का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

आज ज़रूरत इस बात की है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ वातावरण तथा पर्यावरण के बीच सामंजस्य बनाया जाए। अधिकतम उत्पादन, लाभ तथा मृदा की उत्पादकता को लम्बे समय तक स्थिर बनाए रखने के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तकनीक का प्रयोग करना अनिवार्यता बन चुका है। इसमें कार्बनिक खादों, रासायनिक उर्वरकों, जैव उर्वरकों तथा उचित फसल-चक्रों का समावेश किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें पुरानी कृषि पद्धति एवं आधुनिक कृषि प्रणाली को जोड़ते हुए एक नई दिशा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा।

इस समय आवश्यकता है कि वैज्ञानिक एक ऐसी कार्य योजना पर कार्य करें, जिसमें पर्यावरण सहयोगी तकनीकियों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। आज सिर्फ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती। लम्बे समय तक लगातार रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से उत्पादन, उत्पाद की गुणवत्ता तथा भूमि पर हनिकारक प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ लगातार बढ़ती जनसंख्या की खाद्य है।



आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः जैविक खेती से भी संभव नहीं। अतः आज ज़रूरत इस बात की है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ वातावरण तथा पर्यावरण के बीच सामंजस्य बनाया जाए। अधिकतम उत्पादन, लाभ तथा मृदा की उत्पादकता को लम्बे समय तक स्थिर बनाए रखने के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तकनीक का प्रयोग करना अनिवार्यता बन चुका है। इसमें कार्बनिक खादों, रासायनिक उर्वरकों, जैव उर्वरकों तथा उचित फसल-चक्रों का समावेश किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें पुरानी कृषि पद्धति एवं आधुनिक कृषि प्रणाली को जोड़ते हुए एक नई दिशा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा।

वर्मी कम्पोस्ट क्या है?

कैंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन के फलस्वरूप तैयार उत्पाद को ह्यूमस की संज्ञा दी जाती है, जिसका पुनः विघटन ना हो सके।



डॉ. जे.के. नांदल
व डॉ. प्रेमदीप,
कृषि विज्ञान केन्द्र, सोनीपत

उस पदार्थ को वर्मी कम्पोस्ट कहते हैं। कैंचुए कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। यह कार्बनिक पदार्थ कैंचुओं के पाचन-तंत्र से होता हुआ जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। एक महक वाली सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में बाहर जा पदार्थ निकल कर आता है, वह वर्मी कास्ट कहलाता है, अर्थात् साधारण भाषा में कैंचु की विष्ठा (कास्टिंग/मल) को ही वर्मी कम्पोस्ट कहते हैं। यह रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता तथा उनके अधिक उपयोग को घटाने का एक बेहतरीन विकल्प है। साथ ही कस्बों, गांवों तथा शहरों में जैविक रूप से विघटित हो सकने वाले कार्बनिक कचरे के निपटारे का यह एक उत्तम उपाय है। इसे वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली कम्पोस्ट खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। कैंचुओं द्वारा वर्मी कम्पोस्ट बनाने की इस प्रक्रिया को ही वर्मी कम्पोस्टिंग कहते हैं।

जानी हो, तो इसके तल में 8-10 छोटे-छोटे छेद जल विकास हेतु अवश्य बनाएं।

* गड्ढों में वर्मी-कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए एक मीटर लम्बा, एक मीटर चौड़ा तथा आधा मीटर गहरा गड्ढा किसी छायादार स्थान पर बनाएं।

* सबसे निचली सतह पर तीन-साढ़े तीन सैटीमीटर मोटी ईंट या पत्थर की तरह बिछाएं।

* ईंट या पत्थर की परत के ऊपर तीन-साढ़े तीन सैटीमीटर बालू या रेत मिट्टी की तह बनाएं और

* रेत की परत के ऊपर 15 सैटीमीटर तक अच्छी दोमट मिट्टी या सड़ी गोबर की खाद की परत बनाएं।

* इस परत के ऊपर पानी छिड़क कर नम कर लें।

* इसके बाद 100-200 कैंचुए डाल दें।

* नम मिट्टी के ऊपर गले-सड़े गोबर की 5-7 सैटीमीटर मोटी परत बिछा दें।

* गोबर के ऊपर 5-10 सैटीमीटर पुआल/सूखी पत्तियां डाल दें।

* इस इकाई में बराबर 20-25 दिन तक पानी का छिड़काव करें

तथा बोरे आदि से ढक कर रखें। जब कैंचुए ऊपर दिखाई देने लगें, तो पुनः लगभग 5-10 सैटीमीटर कचरे तथा गोबर के मिश्रण की परत लगाएं। यह प्रक्रिया तब तक करें, जब तक कि गड्ढा पूरा भर ना जाए।

* इसमें प्रति दिन अथवा आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करें।

* 40-45 दिन में जब गड्ढे में पूरे पदार्थों की दानेदार व गहरे भूरे रंग की वर्मी-कम्पोस्ट बन जाए, जो दुर्गंध रहित होती है, तब दो से तीन दिन तक पानी का छिड़काव बंद रखें।



**आपकी फसल
की सुरक्षा
... कोपल के साथ**

वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन विधि

कैंचुओं द्वारा खाद उत्पादन के लिए स्थान, छाया की व्यवस्था, पानी, कार्बनिक पदार्थ, गोबर एवं कैंचुओं की आवश्यकता होती है। वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए ऐसी मान्यता रही है कि इसे सिर्फ गड्ढे में या टांकों बना कर ही तैयार किया जा सकता है, परन्तु अब इसके लिए गड्ढा बनाना भी आवश्यक नहीं है। यह कच्ची या पक्की सतह पर छायादार स्थान में तैयार किया जा सकता है। जमीन की सतह पर विच्छी कार्बनिक पदार्थों की ढेरियों की लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपनी सुविधा के अनुसार रखी जा सकती है। सामान्य रूप से ढेरी/गड्ढे की चौड़ाई डेढ़ मीटर से अधिक ना रखें, ताकि हाथ फैलाने पर ढेरी के मध्य तक आसानी से पहुंच जाए और आवश्यकता अनुसार किया जा सके। यदि कम्पोस्टिंग लकड़ी या प्लास्टिक की पेटी में की



Ph. : 9592064102

www.coplgroup.org

E-mail : info@coplgroup.org



नींबूवर्गीय फलों में रस चूसक कीटों की रोकथाम

1. नींबू का सिल्ला : यह नींबू जाति के सभी वृक्षों का एक प्रमुख कीट है। इस कीट के गोल, चपटे एवं नारंगी-पीले रंग के शिशु तथा भूरे रंग के प्रौढ़ नई टहनियाँ और पत्तों से रस चूसते हैं, जिससे पत्ते धीरे-धीरे पीले पड़ कर अंत में सूख जाते हैं। सिल्ला के शिशु, प्रौढ़ की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं। इसके शिशु 10-35 दिन में विकसित होकर प्रौढ़ बन जाते हैं। यह कीट साल भर सक्रिय रहता है। मार्च-अप्रैल तथा वर्षा ऋतु के बाद यह सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। इसके प्रकोप से पैदावार एवं उसकी गुणवत्ता पर विपरीत असर होता है। यह कीट सिट्रस डिक्लाइन रोग के एक प्रमुख कारक हरित रोग (सिट्रस ग्रीनिंग) का वाहक भी है। माल्टा एवं मीठे नींबू पर इसका प्रकोप ज्यादा देखा गया है।

प्रबंधन : कीट का प्रकोप दिखाई देने पर ऑक्सीडेमेटान मिथाइल (मैटासिस्टॉक्स) 25 ई.सी. @ 750 मिलीलीटर या डाइमेथोएट (रोगोर) 30 ई.सी. @ 625 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 500 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें। परागीकरण करने वाले कीटों की रक्षा हेतु फूल आने के समय कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ना करें। नींबू जाति के सभी वृक्षों व बाढ़ की झाड़ियों पर छिड़काव न करें।

2. नींबू का लीफ माइनर : यह भी नींबू के पत्तों को नुकसान



पहुंचाने वाला एक प्रमुख कीट है। यह मुलायम पत्तियों की दोनों सतहों पर चांदी की तरह चमकीली और टेढ़ी-मेढ़ी सुरंगें बनाता है। इसके प्रकोप से पत्तियाँ तथा टहनियाँ कुरुरूप

विनीता राजपूत, ज़िला विस्तार विशेषज्ञ (बागवानी); सतीश कुमार, ज़िला विस्तार विशेषज्ञ (पादप रोग विज्ञान) और नरेन्द्र कुमार, ज़िला विस्तार विशेषज्ञ (मृदा एवं जल संरक्षण), कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरसा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

होकर सूख जाती है। प्रकोपित पत्तियों पर फफूटी पनपने लगती है। मौसम के अनुसार यह कीट 5-30 दिन तक सुरंगों के अंदर रह कर पत्तियों को खाता है। इनका प्रकोप बसंत और मई से अक्तूबर के महीनों में ज्यादा होता है। यह मुलायम व रसदार पत्तियों पर अधिक नुकसान करते हैं तथा नर्सरी में इसके प्रकोप से पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। यह कीट सिट्रस के कैंकर को भी बढ़ाने का काम करता है।

प्रबंधन : बचाव के लिए फैनवेलरेट 20 ई.सी. @ 500 मिलीलीटर या साईपरमैथ्रिन 10 ई.सी. @ 1000 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. @ 200 मिलीलीटर या थाईमेथॉक्सम 25 डब्ल्यू.एस. @ 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 500 लीटर पानी में मिला कर अपैल-मई व सितम्बर-अक्तूबर माह में छिड़काव करें।

3. नींबू की सफेद मक्खी तथा काली मक्खी : सफेद मक्खी के शिशु चपटे तथा हल्के पीले रंग के होते हैं एवं इनके शरीर पर बाल होते हैं। प्रौढ़ मक्खी के शरीर व पंखों पर सफेद रंग का चूर्ण जमा होता है। काली मक्खी के शिशु कांटेदार चपटे अण्डाकार तथा गहरे

में सूख कर गिर जाती है। इन मक्खियों के शिशु 25 से 70 दिनों तक पत्तियों की निचली सतह पर चिपके रह

सी. @ 1250 मिलीलीटर या मैटासिस्टॉक्स 25 ई.सी. @ 1000 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड



कर विकसित होते हैं। यह कीट पूरी गर्भी (मार्च-सितम्बर) सक्रिय रहते हैं, परन्तु इनका प्रकोप मार्च, अप्रैल, अगस्त व सितम्बर में ज्यादा होता है।

प्रबंधन : कीट का प्रकोप दिखाई देने पर ऑक्सीडेमेटान मिथाइल (मैटासिस्टॉक्स) 25 ई.सी. @ 750 मिलीलीटर या डाइमेथोएट (रोगोर) 30 ई.सी. @ 625 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 500 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें।

4. नींबू का माहू : इसके शिशु व प्रौढ़ पौधे की नई पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं और सूख जाती हैं। नए पौधों की बढ़वार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। माहू द्वारा छोड़े गए द्रव्य पर फफूंद जमने लगती हैं और चीटियों का आक्रमण होने लगता है। फूल आने के समय पर यदि इस कीट का प्रकोप हो तो पौधे पर फल बनाना भी कम हो जाता है। यह कीट सिट्रस के ट्रिस्टेजा वायरस का वाहक भी है।

प्रबंधन : डाइमेथोएट 30 ई.

बरसात के मौसम में नींबूवर्गीय फलों में रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। बाग में आस-पास खरपतवार अधिक हो जाने के कारण और वातावरण में अधिक नमी होने के कारण इस प्रकार के कीट संख्या में बढ़ जाते हैं और फसल पर अपना प्रतिकूल प्रभाव छोड़ते हैं। ज़रुरी है कि समय अनुसार इन कीटों का प्रबंधन किया जाए ताकि बढ़ते हुए फलों पर इनका प्रभाव कम किया जा सके। रस चूसक कीट ना केवल फलियों, पत्तियों बल्कि फलों पर भी आक्रमण करते हैं। कुछ कीटों के आक्रमण की वजह से फलों के छिलकों पर धब्बे व निशान बन जाते हैं, जिनसे बाज़ार में फलों का मूल्य अच्छा नहीं मिलता है।

की दर से 500 लीटर पानी में मिला कर पौधों पर मार्च-अप्रैल माह में स्प्रे करें।

6. फलों का रस चूसक पतंगा (मोथ) : इस कीट का प्रौढ़ फलों का नुकसान पहुंचता है। यह बरसाती मौसम में पके हुए फलों से शाम के समय रस चूसते हैं और फलों के ऊपर छोटे काले रंग के धब्बे बनाते हैं। कुछ समय बाद यह धब्बे आकार में बड़े होकर पीले-भूरे रंग के हो जाते हैं। किनू के एक फल पर इस प्रकार के 16 धब्बे तक पाए जा सकते हैं। प्रभावित फलों पर बैक्टीरिया व फफूंद का आक्रमण आसान हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फल गल कर नीचे गिर जाते हैं। यह कीट जुलाई से अक्तूबर माह में सक्रिय होता है।

प्रबंधन : बाग में साफ-सफाई बनाए रखें व खरपतवार न होने दें। नीचे गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। फलों की बैगिंग से भी कीट के प्रभाव से बचा जा सकता है। परन्तु यह बड़े बागों के लिए संभव नहीं है। मोथ को भागने के लिए बाग में धुआं करें। कार्बोरिल



17.8 एस.एल. @ 200 मिलीलीटर या थाईमेथॉक्सम 25 डब्ल्यू.एस. @ 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 500 लीटर पानी में मिला कर मार्च के माह में या कीट के दिखाई देने पर छिड़काव करें।

5. नींबू का तेला : यह नर्सरी में व नए बाग में नींबूवर्गीय वृक्षों का एक गंभीर कीट है। यह बहुत ही महीन होते हैं, जो नग आंखों से दिखाई भी नहीं देते। यह फूलों, पत्तों व छोटे फलों का रस चूस कर उन्हें सुखा देते हैं। पत्तों पर इनके प्रभाव से सफेद रंग की लाइनें दिखाई देती हैं। पत्ते अंदर की तरफ मुड़ कर कप जैसा आकार बना लेते हैं और उनका आकार बिगड़ जाता है। फलों पर गर्दन के हिस्से में भी सफेद रंग के धब्बे व गोलाकार धारियाँ बनने लगती हैं। इस प्रकार के प्रभावित फलों को बाज़ार में अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। यह कीट मार्च-अप्रैल माह में अधिक सक्रिय रहते हैं।

प्रबंधन : ट्राईज़ोफॉस 40 ई. सी. @ 1250 मिलीलीटर प्रति एकड़

50 डब्ल्यू.पी. @ 1 किलोग्राम 500 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से घोल कर फलों के पकने के समय पर छिड़काव करें।

समय-समय पर बाग का निरीक्षण करते रहें, जिससे समय रहते कीटों के प्रकोप से पौधों व फलों को बचाया जा सके।

पौधों की बढ़वार में मिट्टी का सबसे अधिक योगदान होता है। इसलिए अगर आप अपनी बगिया को ढेर पौधों से सजाना चाहते हैं, तो थोड़ा मिट्टी को तैयार करने की जानकारी भी ले लें।

संदीप भारद्वाज

हर पौधे को डागने और बेहतर बढ़वार के लिए अलग-अलग तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनकी पर्ति वे आस-पास मौजूद वातावरण और मिट्टी से करते हैं। चूंकि अब हम घर में या बगीचे में विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे लगा रहे हैं। इसलिए उन्हें उनका मूल वातावरण देना आवश्यक है, जो आप सही मिट्टी बना कर दे सकते हैं। यहां कुछ पौधों के हिसाब से मिट्टी के मिश्रण बताएं गए हैं, जिन्हें आप आजमा सकते हैं।

बाहर लगने वाले पौधे

घर के बाहर आप जिन पौधों को लगाते हैं, उन्हें प्रायः अधिक धूप और वायु की आवश्यकता होती है। इसलिए इनकी मिट्टी में नमी मौजूद होना आवश्यक है। इन्हें लाल मिट्टी में उगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन्हें घर के बगीचे में लगा रहे हैं, तो मिट्टी का सही मिश्रण बना लें। इसके लिए, मिट्टी के 40 फीसदी भाग में फ्लाईट का 10 फीसदी भाग, मोटी रेत का 10 फीसदी भाग और 40 फीसदी ऑर्गेनिक खाद को मिला कर तैयार कर सकते हैं।

घर के अंदर लगने वाले पौधे
इनडॉर प्लांट को अधिक पोषक तत्वों वाली मिट्टी चाहिए होती है। इसलिए इन पौधों को लगाने के लिए 40 फीसदी बगीचे की मिट्टी में 10 फीसदी पलाईट, 10 फीसदी वर्मिक्यूलाइट और 40 फीसदी ऑर्गेनिक खाद मिला कर मिट्टी का मिश्रण तैयार कर सकते हैं।

सेक्यूलैट प्लांट

कैक्टस, एलोवेरा, स्नेक प्लांट और जेड प्लांट जैसे पौधे अपनी जड़ों के साथ-साथ पत्तियों और तनों में भी पानी को संग्रहित करके रखते हैं। इसलिए ये ऐसी मिट्टी में बढ़ते हैं, जिसमें वायु संचार और जल निकासी सुगम हो। घर पर इन पौधों के लिए 40 फीसदी बगीचे की मिट्टी में, 20 फीसदी पलाईट, 15 फीसदी मोटी रेत और 15 फीसदी वर्मिक्यूलाइट को अच्छी तरह से मिला कर मिट्टी तैयार की जा सकती है।

जलीय पौधों के लिए

वॉटर लिली और कमल को आर्द्ध वातावरण चाहिए होता है, जिसे तैयार करने के लिए एक बड़े वृत्ताकार पॉट में 1-1 1/2 डेढ़ इंच वर्मिम्पोस्ट/गोबर खाद डालें, फिर 5-6 इंच मिट्टी डाल कर 5-6 इंच मिट्टी डाल कर 5-6 इंच तक पानी भरें। इस मिश्रण में बढ़वार अच्छी होगी और शैवाल भी नहीं पनपेंगे। जलकुम्भी या पेनीवर्ट जैसे पौधों के लिए पानी की मात्रा कम रखें।

फूलों वाले पौधे

इनके लिए मिट्टी का अम्लीय होना आवश्यक है। फूल वाले पौधों को पर्याप्त धूप और नमी की आवश्यकता होती है। बेहतर वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा की जरूरत पड़ती है। हालांकि पोषक तत्वों और अम्लीयता का अनुपात पौधे की प्रकृति के हिसाब से अलग-अलग होता है, जो कुछ इस



पौधा अलग है तो मिट्टी भी अलग होगी

प्रकार है :

1. सामान्य फूलों वाले पौधों के लिए : गुलाब, कनेर जैसे सामान्य सही मिश्रण 40 फीसदी गमले की

पौधों को लगाने के लिए मिट्टी का मिट्टी में 30 फीसदी पलाईट, 20

फीसदी वर्मिक्यूलाइट और 10 फीसदी ऑर्गेनिक खाद को मिला कर तैयार किया जा सकता है।

2. डेज़ी और पेट्टनिआ जैसे पौधों के लिए : ऐसे पौधे जिनका तना मज़बूत नहीं होता, उन्हें मिट्टी में अम्लीयता कम (पी.एच. 6-7 के बीच) चाहिए होती है। इसलिए इन्हें रोपने या स्थानांतरित करके लगाने के लिए ऐसी मिट्टी चुनें, जिसमें 50 फीसदी बगीचे की मिट्टी हो, 25 फीसदी पलाईट, 15 फीसदी वर्मिक्यूलाइट और 10 फीसदी खाद की उपस्थिति हो।

3. गर्म जलवायु वाले फूलों के पौधे : चांदनी, पेंटास जैसे पौधे गर्मी होने पर अधिक फूलों का उत्पादन करते हैं। इसलिए इनकी मिट्टी में अम्लीयता का स्तर सामान्य (पी.एच. 6) रहता है। इनकी मिट्टी को तैयार करने के लिए 50 फीसदी बगीचे की मिट्टी में 25 फीसदी पलाईट, 15 फीसदी रेतीले पत्थर और 10 फीसदी ऑर्गेनिक खाद मिलाएं।

EICHER TRACTORS



पावर | परफॉरमेंस | स्टाइल एक साथ

TAFE CORPORATE COMMUNICATIONS

EICHER 485

45 hp रेंज

पावरफुल 45 hp इंजन

मल्टी स्पीड / रिवर्स PTO

डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर

EICHER 485

45 hp रेंज

संग्रहित अनाज में माईट समस्या तथा प्रबंधन



में अधिक हो जाता है, तब ये बड़ी भारी मात्रा में भूरे रंग के चलते-फिरते

माईट का प्रकोप संग्रहित आनाज के भंडारण गृहों में सामान्य तौर पर देखा जाता है। प्रायः ऐसे भंडारण गृह जहां आनाज का संग्रहण नम व आद्र दशाओं में किया जाता है अथवा आनाज में अधिक नमी होती है, तो भी माईट के प्रकोप में बड़ी वृद्धि होती है। आनाज संग्रह के दौरान इन माईट का उपद्रव दलहन, तिलहन, आनाज, उनके उत्पादों तथा पशु आहार आदि में बड़े पैमाने पर होता है। संग्रहित आनाज में माईट का ये प्रकोप हमें प्रायः दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि इन माईट का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है तथा धूल के समान होती है। यहां ये बात स्पष्ट करनी अत्यंत आवश्यक है कि माईट को कई बार हम कीट समझ बैठते हैं, परन्तु ये कीट नहीं हैं बल्कि चिचड़ी तथा मकड़ी की नज़दीक के रिशेतदार हैं। कीटों के विपरीत, माईट में चार जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जब कभी माईट का उपद्रव संग्रहित आनाज

माह इनकी संख्या में 500 गुना तक वृद्धि होती है। गर्म व नमी युक्त वातावरण में बड़ी ही तेज़ी से वृद्धि करने के कारण इनकी संख्या गर्मी के मौसम में बहुत ही अधिक हो जाती

तालिका : आनाज को ग्रसित करने वाली माईट प्रजातियाँ

क्र.	माईट	वैज्ञानिक नाम
1.	मोल्ड माईट	टायरोफेगस पूटीसीएन्स
2.	आनाज की माईट/आटे की माईट	ऐसीरिया सीरा
3.	खुजली माईट	पायोकोटस ट्रिटीसाइ
4.	बल्ब माईट	राईजोग्लाईफ्स रोबीनी
5.	स्केली ग्रेन माईट	सूडेसिया नेसबीटी
6.	सूखे फल की माईट	कार्पोग्लाईफ्स प्रजाति
7.	हे माईट	लेपीडोग्लाईफ्स डिस्ट्रक्टर
8.	चीज़ माईट	टायरोफेगस नेस्वेन्डीरी

है। प्रायः तटीय इलाकों जहां पर अधिक का जीवन-चक्र अत्यंत ही रोचक होता है, इनका उपद्रव अधिक होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी सामग्री जिनमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इन माईट की वृद्धि के लिए आदर्श परिस्थिति पैदा करती है, जिनसे इनकी संख्या में बड़ी ही तेज़ी से बढ़ोत्तरी होती है।

माईट से नुकसान : प्रायः मोल्ड तथा दाने की माईट आनाज के वृद्धि भाग (जर्म वाले भाग) को खाकर सीधे तौर पर नुकसान करती है। इसी के साथ ये तेज़ी से मृतोपरजीवी फफूंदी को इस संग्रहित आनाज में फैलती है, जिससे संग्रहित आनाज से खराब गंध आने लगती है। इसमें माईट व अन्य जीवों के शरीर भी सड़-गल जाते हैं, जोकि आनाज को और भी अधिक खराब करते हैं। मोल्ड माईट के भारी उपद्रव के कारण इनकी संख्या गर्मी के मौसम में बहुत ही अधिक हो जाती है।

करके उन्हें जला देना चाहिए। समय-समय पर गोदामों की साफ-सफाई करनी चाहिए, इस हेतु धूल, आनाज के पाऊडर आदि को साफ करना चाहिए। आनाज को लाने ले जाने वाले साधनों, उपकरणों आदि की समय-समय पर साफ-सफाई करनी चाहिए।

2. तापमान तथा नमी प्रबंधन

: संग्रहित आनाज की माईट की वृद्धि के लिए गर्म तथा नम वातावरण की आवश्यकता होती है। इसी में कुछ बदलाव करके भी माईट की संख्या में कमी लाइ जा सकती है। गोदामों में वायु का संचरण करके तापमान को कम रख कर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना चाहिए। इसी प्रकार से नमी को 55 प्रतिशत तक रख कर भी माईट की संख्या को कम किया जा सकता है। आनाज को भी भंडारित करने से पूर्व उनकी नमी को 12 प्रतिशत से कम करने से भी माईट के प्रकोप को कम किया जा सकता है।

3. गोदामों को सीलबंद करके उनमें अनुरासित दवा से प्रधूमित करना चाहिए, इससे वयस्क माईट तथा उनकी अपरिक्व अवस्थाएं भी नष्ट हो जाती हैं।

4. आनाज की बोरियों में नया आनाज भरने से पूर्व उन्हें गर्म पानी में 15 मिनट तक डुबोना चाहिए। इन बोरियों को मैलाथियान 50 ई.सी. से भी उपचारित करके उनमें आनाज का भंडारण करना चाहिए।

शेष पृष्ठ 5 की

वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग करें

कर दें। इससे केंचुए नीचे की परत में चले जाएंगे।

केंचुआ : केंचुआ एनिलिडा वर्ग का रात्रिचर जीव है। अतः यह अंधेरे व रात्रि में अधिक क्रियाशील रहता है। यह तापमान के अनुसार बरसात में 30-50 सैटीमीटर गहराई पर तथा सर्दियों में 100 से 130 सैटीमीटर गहराई तक भूमि में रहता है। साधारणतया यह 10 वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी प्रजनन क्षमता 2 से 2.5 वर्ष तक ही रहती है। 6 माह बाद इससे कोकून प्राप्त होने लगता है। एक कोकून से 2-3 सप्ताह में एक वयस्क बाहर निकलता है। 6 माह में एक जोड़े केंचुए से लगभग 100 कोकून प्राप्त किए जा सकते हैं। ये धनिया के बीज के आकार के 3-4 मिलीमीटर लम्बे, 3-10 मिलीग्राम वज़न के प्रारम्भ में सफेद तथा बाद में भूरे कर्त्तव्य रंग के हो जाते हैं। इन 800 से 1000 केंचुओं का वज़न लगभग 1 किलोग्राम तथा कीमत लगभग 200 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम या प्रति एक हज़ार केंचुए होती है। अच्छी वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए लगभग 25-30 सैलिस्यस तापमान उपयुक्त होता है। साधारणतः एक केंचुआ अपने वज़न के बराबर कार्बनिक पदार्थ प्रति दिन खाता है। यह 25 सैटीमीटर प्रति मिनट की गति से चलता है।

* यह पेड़-पौधों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं सभी प्रकार की फसलों के लिए एक सम्पूर्ण एवं संतुलित आहार है।

* वर्मी कम्पोस्ट पेड़-पौधों की सेहत एवं उनकी वृद्धि में सहायक है, जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। यह खरपतवारों, कीटों एवं रोगों पर होने वाले खर्च में भी कमी लाता है।

* इसके प्रयोग से भूमि की जलशोषण तथा जलधारण क्षमता बढ़ती है। भूमि की भौतिक दशा में सुधार आने से उसमें रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाएं तेज़ी से होने लगती हैं।

* वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग से बहुत सारे कार्बनिक कचरे से मुक्ति मिल सकती है, जो वर्तमान में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इससे मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के साथ-साथ आर्थिक बचत भी होगी। पॉलीथीन बैग, लोहा व कांच को छोड़ कर केंचुए समस्त कार्बनिक कचरे को खाद बना देते हैं।

उपरोक्त प्रौद्योगिकी को किसान एवं नौजवान अपनी खेती को टिकाऊ बनाने व स्वरोज़गार के लिए अपना सकते हैं। इससे जहां एक ओर ग्रामीण युवाओं को रोज़गार मिलेगा, वहीं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फैले कार्बनिक कचरे का खाद बना देता है। इसके अतिरिक्त यूडिलस यूजिनिया तथा पेरिआनिक्स एक्सावेट्स आदि प्रजातियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यूडिलस यूजिनिया तथा पेरिआनिक्स एक्सावेट्स आदि प्रजातियों का भी प्रयोग किया जाता है।

वर्मी कम्पोस्ट के लाभ :



खेती दुनिया

द्वारा

किसान भाईयों व डीलर/डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए
चंदों में विशेष छूट

एक वर्ष 400/- रुपए

दो वर्ष 700/- रुपए

पेमेंट करने के पश्चात् अपना डाक पता इस नंबर पर भेजें :

90410-14575



चंदे भेजने हेतु QR कोड स्कैन करें।

हमारे देश की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक प्रकाश-पुंज की तरह है, जो विकसित भारत की दिशा में हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों के रूप में प्रतिबिम्बित होता है। अब यह क्षेत्र केवल अर्थव्यवस्था में योगदानकर्ता भर नहीं रह गया है, बल्कि तेजी से भारत की विकास गाथा का आधार बनता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में नीतियों, पहलों और बुनियादी ढांचे के विकास के बेहतरीन मिश्रण ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, जिससे यह वैश्विक मंच पर एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। वर्तमान में भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर वाली समृद्ध अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2047 में देश की स्वतंत्रता की शताब्दी तक 30-35 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनना है।

भारत में हो रहे बदलावों के मूल में इसकी समृद्ध कृषि-जलवायु विविधता है, जो हमारे किसानों को विभिन्न प्रकार की विशिष्ट फसलें उगाने में सक्षम बनाती है। दालें, मोटे अनाज, दूध, गेहूं, चावल तथा फलों और सब्जियों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश होने के रूप में, भारत के पास मूल्य वर्धन के लिए संसाधनों का अद्वितीय आधार मौजूद है। हमारे मेहनतकश किसानों द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित इस कृषि प्रचुरता ने नवाचार और उद्यमिता के दौर को जन्म दिया है, जिससे उन्नतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उदय हुआ है।

यह क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का आधार बन चुका है, जो रोजगार के अवसरों के सृजन, तकनीकी प्रगति और बाजार के नए अवसरों के निर्माण के माध्यम से विकास को गति दे रहा है। भारत शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी और सबसे युवा कामकाजी आबादी होने का भी दावा करता है, जिससे इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को और बढ़ावा मिलता है। उन्नत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, इस उद्योग ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, उत्पाद की शैलफ लाइफ बढ़ाने और किसानों को उनके प्रयासों के लिए बेहतर



विकसित भारत के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बदलाव

रिटर्न दिलाना सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जैसे-जैसे विकसित हो रहा है, यह न केवल गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कसौटी पर खरा उत्तर रहा है, बल्कि वैश्विक उपभोक्ताओं की लगातार बदलती पसंद और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पेशकशों में विविधता भी ला रहा है। इस प्रकार कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बीच का घनिष्ठ साधन का रूप ले चुका है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे किसान और कृषि देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत के कृषि उत्पाद दुनिया के कोने-कोने में संवर्धित मूल्य और गुणवत्ता के साथ पहुंचे। ऊर्जावान और युवा कार्यबल द्वारा समर्थित इस एकीकरण के माध्यम से, हम इस सशक्त, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के उद्भव का साक्षी बन रहे हैं जो भारत को एक समृद्ध और एकाऊ भविष्य की ओर ले जाने के लिए तपत है।

एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में, कोविड-19 महामारी ने इस क्षेत्र के प्रभावशाली लचीलेपन को दर्शाया, किसानों को उनके प्रयासों के लिए बेहतर



रवनीत सिंह बिट्टू
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
राज्य मंत्री, भारत सरकार

सहायता प्रदान करता है।

इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) सबसे अग्रणी है, जो पीएम किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का समर्थन कर रहा है। यह पहल अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करके और खेत से लेकर खुदरा तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करके इस क्षेत्र को बदल रही है। इन प्रयासों को पूर्णता प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता निर्माण और विपणन में सहायता के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास को बढ़ावा देती है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) वृद्धिशील बिक्री से जुड़े वित्तीय पुरस्कारों की पेशकश करके घेरलू विनिर्माण एवं निर्यात वृद्धि को और बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपये का विशेष अवसंरचना कोष इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आवश्यक है। यह किसानों के लिए बेहतर दामों की प्राप्ति भी सुनिश्चित करते हुए और बाजार के अवसरों में वृद्धि करते हुए, जीडीपी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और आजीविका में

करता है, जो मजबूत, एकीकृत और दूरंदेशी विकास पथ सुनिश्चित करता है।

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इसका जनसाधारिकीय लाभांश खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नई ऊंचाइयों को छूने के अनुठे और अभूतपूर्व अवसरों का सूजन करता है। सरकार के महत्वपूर्ण कर संबंधी प्रोत्साहनों, कारोबार करने में सुगमता की सुव्यवस्थित पहल और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास सहित दूरदर्शी व्यवसाय समर्थक सुधारों ने निवेश और विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया है। यह सहयोगपूर्ण परिदृश्य न केवल वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है बल्कि भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार और विस्तार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी स्थापित करता है।

वर्ष 2023 में पिछले संस्करण की शानदार सफलता के बाद, मंत्रालय 19 से 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में खाद्य उद्योग के हर पक्ष से जुड़े हितधारक विचारों का आदान-प्रदान करने, अवसरों का अन्वेषण करने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने के लिए एक साथ आएंगे। यह एक अनोखा सम्मेलन होगा जिसमें दुनिया भर के खाद्य इकोसिस्टम से जुड़े निर्माता, उत्पादक, निवेशक, नीति-निर्माता और संगठन शामिल होंगे।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 एक ऐसा मंच है, जहां हितधारक नवाचारों का अन्वेषण करने, साझेदारी बनाने और इटिकाऊ खाद्य भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। आइए, हम अपने सामने मौजूद अवसरों का लाभ उठाएं तथा अधिक समृद्ध और लचीली खाद्य प्रणाली की दिशा में ऐसी यात्रा की शुरुआत करें, जो मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों को लाभान्वित करे। सामंजस्य के इस दौर में, हम न केवल एक उद्योग को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे भविष्य के साझा विजय को भी अंगीकार कर रहे हैं जहां नवाचार, स्थिरता और समृद्धि हमारे देश के कोने-कोने का उत्थान करें।

चाहतो है कि घर के आगे सुंदर—सा बगीचा हो या फ्लैट में खूबसूरत फूलों से सजी बालकनी पर ऐसा हर मौसम में कहाँ मुस्किन हो पाता है। खुश हो जाइए क्योंकि ऐसे सदाबहार पौधों हैं, जो आपका यह खाब पूरा कर सकते हैं।

ज्यादातर फूल वाले पौधे मौसम के अनुकूल होते हैं, इसलिए लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि मौसम बदलते ही वे सूखे जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जो हर मौसम में ना केवल लगाए जा सकते हैं, बल्कि सालभर उनमें फूल भी आते रहते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती। आइए जानते हैं इन पौधों व इन्हें लगाने के सही तरीकों के बारे में।

सही पौधों का चुनाव : सदाबहार बगिया के लिए सही पौधों का चयन सबसे ज़रूरी है। बोगनवेलिया, गुड़हल, चमेली, अपराजिता, रातरानी, सदाबहार, अडेनियम और गुलाब कुछ ऐसे ही पौधे हैं, जिन्हें एक बार लगाने पर कई साल तक ये हरे-भरे रह कर अपनी महक बिखेरते रहते हैं।

सबसे अच्छी बात ये है कि सालभर में किसी भी समय ये पौधे लगाए जा सकते हैं। इनकी मदद से आप अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद बागवानी के शौक को आसानी से पूरा

सदाबहार पौधों से गुलजार रहेंगी बित्तिया

कर सकते हैं।

अपराजिता : तेजी से बढ़ने वाली अपराजिता बेल या विष्णुकांता का पौधा सालभर चलने वाला पौधा है। इसे बीज और कलम दोनों की मदद से गमले या ज़मीन में लगाया जा सकता है। इसमें नीले और सफेद रंग के फूल खिलते हैं। हल्की धूप और रोशनी में ये फूल घर के अंदर भी खिल सकते हैं।

बोगनवेलिया : यह पूरे साल बगिया की शोभा बढ़ाता है। बोगनवेलिया सफेद, गुलाबी, पीले सहित कई रंगों में मौजूद रहता है। यह एक सदाबहार पौधा है, जो खुली हवा और गर्म-शुष्क जलवायु पसंद करता है। नर्सरी से इसका तैयार पौधा खरीद कर या फिर कलम की मदद से भी इसे लगाया जा सकता है।

गुड़हल : इस पौधे में सफेद, पीले, लाल और गुलाबी रंग के फूल लगते हैं। साल भर खिलने के कारण ज्यादातर घरों में इसे बहुत पसंद किया जाता है। बीज के अलावा कटिंग की मदद से भी यह सरलता से लगाया जा सकता है। यह गमले में भी आसानी से लग जाता है और ज़मीन में भी खूब फलता-फूलता है।

चमेली : चमेली के पौधों को ज्यादातर

कलम काट कर लगाया जाता है। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं, परन्तु कुछ किस्में पीले, नीले व गुलाबी रंग के फूल को भी होते हैं। इसी तरह रातरानी, डेसीना, ट्रैपेट जैसे पौधों को भी कलम की मदद से लगाकर सदाबहार हरियाली का आनंद उठा सकते हैं।

सदासुहागन : यह बारहमासी फूल है। इसे अधिक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें

पेयजल की बढ़ती कमी में विगत कुछ वर्षों से वर्षा का बदलता प्रतिरूप काफी हद तक जिम्मेदार है। अनियमित एवं कम बारिश तथा बढ़ते तापमान के कारण सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। औद्योगिक व शहरी उपयोग के साथ भारत की 60 प्रतिशत से अधिक कृषि और 85 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है। देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत मांग का आपूर्ति पर भारी पड़ना असंतुलन का दायरा कई गुण बढ़ा देता है।

जल, जिसे जीवन भी कहा जाता है, किसी वरदान से कम नहीं है। इसके बिना जीने की कल्पना भी असंभव है। भारत, जो विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या का निवास स्थान है, कुल वैश्वक भूजल का एक-चौथाई से अधिक उपयोग करता है। यदि पेयजल की उपलब्धता की बात करें तो वर्तमान में भारत के पास विश्व के मीठे जल संसाधनों का मात्र 4 प्रतिशत मौजूद है। देश की आवश्यकताओं को देखते हुए इसे चुनौतीपूर्ण स्थिति कहा जा सकता है। 'जल संचय जन भागीदारी पहल' की शुरुआत पर प्रधानमंत्री भी इसी विषय पर चिंता प्रकट करते नजर आए। घटते भूजल स्तर के म्हेनजर देश के प्रत्येक नागरिक को इसका दुरुपयोग रोकने और पुनर्वर्क्षण के मंत्र को अपनाने की जरूरत है।

जल संकट कमोबेश समूचे देश को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। देश के अनेक हिस्से जल उपलब्धता से वंचित हैं। बीते दिनों दिल्ली और बैंगलुरु में पानी की भारी किल्लत देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी के कई क्षेत्र ड्राई जॉन घोषित किए गए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 60 करोड़ भारतीय जल संकट का सामना कर रहे हैं। सुरक्षित जल की अपर्याप्त पहुंच के कारण प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च, 2021 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 9.14 करोड़

दीपिका अरोड़ा
प्रतिशत जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत पर अप्रयोग के साथ भारत की 60 प्रतिशत से अधिक कृषि और 85 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है। देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत मांग का आपूर्ति पर भारी पड़ना असंतुलन का दायरा कई गुण बढ़ा देता है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के चलते अकारण जल रिसाव, वितरण में हालात उत्पन्न हो रहे हैं। औद्योगिक व शहरी उपयोग के साथ भारत की 60 प्रतिशत से अधिक कृषि और 85 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है। देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत मांग का आपूर्ति पर भारी पड़ना असंतुलन का दायरा कई गुण बढ़ा देता है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के चलते अकारण जल रिसाव, वितरण में हालात उत्पन्न हो रहे हैं। औद्योगिक कचरा, विविध रसायन, सीवेज और घरेलू अपशिष्ट जल स्रोतों में फेंकने अथवा आसापास डंप करने से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे शुद्ध जल की मात्रा से अधिक आबादी जल संकट से जूझेगी। डीसीएम श्रीराम और सत्त्व नॉलेज की मार्च, 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक देश के 50 प्रतिशत से अधिक जिलों में पानी की समस्या बढ़ सकती है। इस दौरान प्रति व्यक्ति पानी की मांग में 30 प्रतिशत और उपलब्धता में 15 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, यदि यही स्थिति रही तो 2050 तक देश में मौजूद जल का 40 प्रतिशत हिस्सा असमाप्त हो सकता है।

असमानता, अकुशल सिंचाई, अत्यधिक दोहन और जल संरक्षण के उपायों की कमी ने भी जल संकट बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



ख्वच्छ जल का संकट

उपलब्धता के साथ गुणवत्ता भी है जरूरी



जल से वंचित है। 21 प्रतिशत संचारी रोग असुरक्षित जल से जुड़े हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है, जहां

लगभग 70 प्रतिशत जल संदूषित है।

जल प्रदूषण और दुरुपयोग का यह सिलसिला यूं ही जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश की आधे से अधिक आबादी जल संकट से जूझेगी। डीसीएम श्रीराम और सत्त्व नॉलेज की मार्च, 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक देश के 50 प्रतिशत से अधिक जिलों में पानी की समस्या बढ़ सकती है। इस दौरान प्रति व्यक्ति पानी की मांग में 30 प्रतिशत और उपलब्धता में 15 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, यदि यही स्थिति रही तो 2050 तक देश में मौजूद जल का 40 प्रतिशत हिस्सा असमाप्त हो सकता है।

जल संरक्षण के संदर्भ में नियम-कानून बने होने तथा केंद्र-राज्य सरकारों द्वारा जल संरक्षण के प्रति जन जागृति फैलाने के लिए 'अटल भूजल योजना', 'कैच द रैन' और 'जल जीवन मिशन' जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके यदि हालात न सुधरें, तो स्पष्ट तौर पर न तो लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं और न ही नियम-कानूनों का समुचित क्रियान्वयन संभव हो सकता है।

जाए कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, प्रकृति संरक्षण भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा रहा है। जल संचय केवल नीतियों तक सीमित न होकर एक पुण्यकर्म भी है, जिसमें उदारता और उत्तरदायित्व दोनों समाहित हैं। दूसरे शब्दों में, जल संरक्षण सामाजिक निष्ठा का भी विषय है, जिसका पालन हमारे पूर्वजों के लिए सर्वोपरि रहा। जल संकट एक स्वास्थ्य संकट है, और प्रत्येक नागरिक के लिए इसे समझना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के कथनानुसार, यदि 'रिड्यूस', 'रियूज', 'रिचार्ज' और 'रिसाइकिल' अपनी दिनचर्या के अभिन्न भाग बना लिए जाएं, तो निस्संदेह हर बूँद सहेजने का यह प्रयास संजीवनी बनकर कितने ही लोगों का जीवन बचा सकता है। इससे बढ़कर परोपकार और क्या हो सकता है!

Rise.
Mahindra

**BIG ON FEATURES. BIG ON SAFETY.
BIG ON SAVINGS.**

RAJ VEHICLES PVT. LTD.

RAJ GROUP

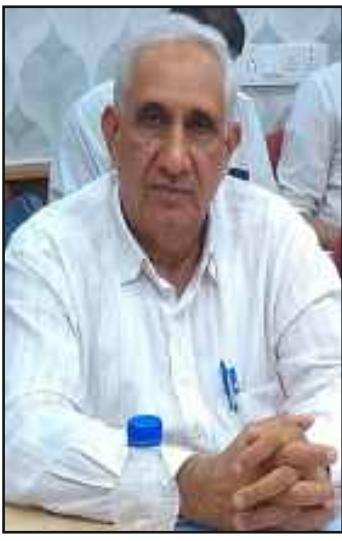
PATIALA
Hira Bagh, Rajpura Road
M. 92163-83180

SANGRUR
Near India Oil Depot,
Mehlan Road

BARNALA
Opp. Grand Castle Resort,
Raikot Road

MALERKOTLA
Near Gaunspura,
Ludhiana Road

Sport Utility Vechiles



डॉ. वीरेन्द्र सिंह लाठर,
पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय
कृषि अनुसंधान संस्थान, नई
दिल्ली (मो. 94168-01607)

सरकार और बिचौलियों के आर्थिक शोषण से बचने के लिए ही किसान वर्ष 2020 से समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने और समर्थन मूल्य सी-2 कुल लागत पर घोषित किए जाने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं।



अब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में भी है। लेकिन बिचौलियों और साहूकारों की हितैषी सरकार वर्षों से किसानों को बहानेबाजी से भ्रमित करती रही है। वही विपक्षी कांग्रेस अप्रासंगिक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बार-बार मांग उठाकर, देश के किसानों को भ्रमित कर रही है। वही विपक्षी कांग्रेस अप्रासंगिक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बार-बार मांग उठा कर, देश के किसानों को भ्रमित कर रही है। क्योंकि 5 खंडों में हजारों पेज पर आधारित सैकड़ों सिफारिशों वाली 'स्वामीनाथन रिपोर्ट' में कही भी फसल समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने की सिफारिश नहीं की गई है।' फिर कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाले केन्द्र ने इस आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया था। यहां तक कि तत्कालीन कृषि मंत्री के.वी. थामस ने सदन में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, एम.एस.पी. और उत्पादन लागत को तकनीकी तौर पर जोड़ना किसानों को उल्टा भी पड़ सकता है।

पिछले 56 वर्षों से सरकार विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर रही है, जिसका लाभ कुछ फसलों की सरकारी खरीद पर लगभग 10 प्रतिशत किसानों को मिल रहा है, बाकी 90 प्रतिशत किसान समर्थन मूल्य से कम पर फसल उपज बेचने वाले देश के 12 करोड़ किसानों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए वार्षिक से ज्यादा और समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं बनने से, समर्थन मूल्य से कम पर फसल उपज बेचने वाले देश के 12 करोड़ किसानों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए वार्षिक नुकसान होता है। दूसरी ओर शोषणकारी सरकार, 500 रुपए प्रति माह की दिखावटी पैशन किसान सम्मान निधि से किसानों को बहका रही है। सरकार और बिचौलियों द्वारा किए जा रहे इस भारी आर्थिक शोषण के कारण ही देश का किसान कर्जबन्दी और ग्रामीण युवा खेती छोड़ कर

दिखावटी पैशन नहीं एम.एस.पी. गर्जटी कानून - किसानों को आर्थिक शोषण से बचाएगा

और समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं बनने से, समर्थन मूल्य से कम पर फसल उपज बेचने वाले देश के 12 करोड़ किसानों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए वार्षिक से ज्यादा और समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं बनने से, समर्थन मूल्य से कम पर फसल उपज बेचने वाले देश के 12 करोड़ किसानों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए वार्षिक नुकसान होता है। दूसरी

ओर शोषणकारी सरकार, 500 रुपए प्रति माह की दिखावटी पैशन किसान सम्मान निधि से किसानों को बहका रही है। सरकार और बिचौलियों द्वारा किए जा रहे इस भारी आर्थिक शोषण के कारण ही देश का किसान कर्जबन्दी और ग्रामीण युवा खेती छोड़ कर

मिलने का मुख्य कारण किसान और उपभोक्ता के बीच बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला है, जो आमतौर पर कृषि विपणन के लाभ का बड़ा हिस्सा हड्डपकर किसान और उपभोक्ता दोनों का शोषण करते हैं।

खुद सरकार, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण मापदंडों की अवेहलना करते हुए, वर्षों से सी-2 कुल लागत से कम पर समर्थन मूल्य घोषित करके किसानों का खुला शोषण कर रही है। दुनियाभर में अनुमान लगाया गया है कि 2000 से 2016 तक भारतीय किसानों को अपने कृषि उत्पादन के उचित मूल्य नहीं मिलने से 2017-18 की कीमतों के आधार पर 45 लाख करोड़ रुपए (600 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान हुआ, जिसके कारण भारतीय कृषि आर्थिक तौर पर घाटे का व्यापार बनी हुई है और हरित क्रान्ति में अग्रणी सघन कृषि उत्पादक प्रदेश हरियाणा और पंजाब के ग्रामीण युवा पुश्तैनी कृषि व्यवसाय छोड़कर, विदेश में मज़दूर बनने पर मज़बूर हो रहे हैं, जो देश के कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित होगा।

भारत में सदियों से कृषि उपज को औने-पौने दाम पर खरीद कर बिचौलिए और रजवाड़े, किसानों का भारी आर्थिक शोषण करते आ रहे हैं, जो देश में लागू किए गए कृषि विपणन सुधारों के बावजूद, आज भी बदस्तूर जारी है। आधुनिक काल में, सर छोटूराम को कानून बना कर कृषि विपणन सुधार लागू करने का जनक माना जाता है। उन्होंने 1939 में पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एकट पास करवाया। इस कानून के तहत पहली बार मार्केट कमेटी का गठन किया गया, इसका काम मंडी के कामकाज को सुचारू रूप से जारी रखना था। बाद में धीरे-धीरे सभी राज्यों ने ए.पी.एम.सी. एकट लागू किया और कृषि मंडी को रेग्युलेट किया गया।

सर छोटूराम ने ही, भारत में सबसे पहले सरकारी खरीद के लिए फसल उपज के समर्थन मूल्य व्यवस्था की थी। उन्होंने राजनीतिक दबाव बना कर द्वितीय विश्व के दौरान 1942 में समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के लिए गेहूं की प्रतिस्पर्धी कीमतें 11 रुपए मन (27.5 रुपए प्रति किंवंटल) वायसराय लार्ड वेवेल से निर्धारित करवाई थी, जबकि वायसराय मात्र 6 रुपए मन पर गेहूं खरीदने के लिए अड़े हुए थे, जिससे उस समय किसानों को सरकार और बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सका था। लेकिन दुर्भाग्य कि आजादी के बाद की सभी सरकारों ने कृषि विपणन उपज मंडी कानून और देश में मांग से कम कृषि उपज होने के बावजूद बिचौलियों को किसानों का शोषण करने की खुली छूट दी। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं

साथ खेती की लागत कई गुना बढ़ी। इस बढ़ी हुई खेती लागत की भरपाई के लिए सरकार ने 1966-67 में एल.के. झा कमेटी की सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग बनाया और फसल समर्थन मूल्य नीति को बिना कानून बनाए लागू किया।

फसल उपज की सरकारी खरीद कछु फसलों और राज्यों तक ही सीमित रही, इसलिए फसल समर्थन मूल्य नीति का फायदा लगभग 10 प्रतिशत किसानों को मिला। देश के बाकी 90 प्रतिशत किसानों के लिए 23 फसलों पर समर्थन मूल्यों का वार्षिक घोषणा पत्र केवल कोरा कागज ही साबित हुआ, क्योंकि वो पिछले 57 वर्षों से अपनी फसल उपज समर्थन मूल्य पर घोषित किया जाता है। 1997 में अभिजीत सेन कमेटी और फिर राष्ट्रीय किसान आयोग-2004 ने समर्थन मूल्यों की गणना सी-2 कुल लागत पर करने की सिफारिश की। वर्ष 2011 में महाराष्ट्र से सांसद श्री राजू शेट्री ने समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनावाने के लिए प्राइवेट बिल संसद में रखा। लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दबाव में, सरकार ने समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने और सी-2 लागत पर समर्थन मूल्य घोषित करने की दिशा में सकारात्मक कदम नहीं उठाए, जिसके दुष्प्रभाव से किसानों में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। अब किसान सरकार और बिचौलियों के आर्थिक शोषण से बचने के लिए समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने और सी-2 लागत पर समर्थन मूल्य घोषित करनावाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं।

पिछले 5 दशकों में कई गुना कृषि उत्पादन बढ़ने के बावजूद, देश अभी तक दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है और गेहूं-धान का उत्पादन भी घरेलू खेत के लगभग बराबर हो रहा है।



आजादी के बाद 25 वर्षों तक देश को बहुत गम्भीर खाद्य स्थिति से गुजरना पड़ा। भारत की मात्र 45 करोड़ जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए सरकार 10 मिलियन टन गेहूं वार्षिक पी.एल. 480 स्कीम में अमेरिका से मुफ्त दान में लेने के लिए मज़दूर ही। ऐसे हालत में 1965-72 के दौरान, दुनियाभर में हरित क्रान्ति के जनक डॉ. नोरमेन बोरलॉग की मदद से गेहूं-धान की बौनी किस्में और रासायनिक उर्वरक अपनाने से देश में हरित क्रान्ति का आगज हुआ, जिसकी बदौलत देश की 3 गुना बढ़ी आबादी के बावजूद, भारत खाद्यान्न आयतक से निर्यातक देश बना। देश में अनाज फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने के होगा। इसलिए सरकार इन फसलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर बार-बार मज़बूर हुई है, इसलिए देश की खाद्य सुरक्षा को टिकाऊ तौर पर सुनिश्चित करने और किसानों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए सरकार को कपटी आंकड़ेबाजी से भ्रमित समर्थन मूल्य घोषणा करने की बाबी आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी खरीद कानून और सी-2 लागत पर समर्थन मूल्य की घोषणा जैसे नीतिगत सुधार लागू करने चाहिए। एम.एस.पी. गारंटी कानून लागू करने से ही किसानों को आर्थिक शोषण से बचाया जा सकेगा और देश की टिकाऊ खाद्य सुरक्षा व फसल विविधीकरण सुनिश्चित करना सम्भव होगा।

गोगामेडी पशु मेले में 81 हज़ार रुपये में बिका सबसे महंगा ऊंट

हरियाणा की सीमा से सटे राजस्थान के गोगामेडी पशु मेले में इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले ऊंटों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। देश के बड़े मेलों में शुमार गोगामेडी पशु मेले में अन्य पशुओं की बजाय ऊंट ही आते हैं।

मेले में हरियाणा, राजस्थान, यू.पी., जम्मू-कश्मीर से ऊंट व्यापारी व किसान अपने ऊंटों को लेकर आते हैं। एक माह तक चलने वाले मेले में इस बार अब तक कुल 3785 ऊंट आए हैं।

इनमें से राजस्थान से 3077 तथा अन्य राज्यों हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर आदि से 708 ऊंट आए हैं। अब तक 972 ऊंटों की बिक्री हुई है। पिछली बार साल 2023 में इस अवधि में 2644 ऊंट आए थे, जिससे पशु-पालन विभाग राजस्थान



गोगामेडी मेले में ऊंटों को लेकर जाते किसान।

को 10349 रुपये की आमदनी हुई ऊंट 81000 रुपये में बिका है। मात्र 9000 रुपए में बिका। पशु-पालन सबसे कम कीमत का ऊंट विभाग से मेला अधिकारी गोगामेडी

कैम्प के व्यवस्थापक डॉ. हरिशचंद्र गुप्ता ने बताया कि इस बार साल 2023 के मुकाबले ऊंटों की आवक ज्यादा है। पिछली बार इसी अवधि में 2644 ऊंट आए थे, लेकिन इस बार अब तक 3785 ऊंट पहुंच चुके हैं। यह मेला 18 सितम्बर तक चलेगा। 11 और 12 सितम्बर को पशु प्रतियोगिता करवाई गई।

जिसमें ऊंटों की दौड़, घुड़ दौड़, भैंस की दूध प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिता करवाई जाएँगी। किसान व व्यापारी जोरा सिंह, सुल्तान सिंह, महेन्द्र सिंह, मनफूल, हरी सिंह ने बताया कि साल 1958 से लगाने वाला यह मेला पशु मेले के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन ऊंट ही ज्यादा आते हैं।

जैविक तरीकों से पैदावार बढ़ाव्ह

करेले की खेती से अच्छी कमाई

फसल पर दूध, कच्ची लस्सी का छिड़काव बढ़ाता है उत्पादन : जतिंदर

किसान जतिंदर सिंह ने पारम्परिक खेती की सीमाओं को पार करते हुए जैविक खेती के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया। 8 वर्षों से जैविक तरीके से खेती करते हुए उसने न केवल अपनी फसल की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि अच्छी कमाई भी सुनिश्चित की। उसके खेतों से प्रति दिन लगभग आधा क्रिंटल करेला पैदा हो रहा है, जो बाजार के रेट से 5-6 रुपए अधिक मूल्य पर बिकता है।

उनका कहना है कि उन्होंने अपने खेत में करेला, कदू और लौकी की खेती शुरू की। इन फसलों पर उर्वरकों के बजाय दूध और कच्ची लस्सी का छिड़काव किया जाता है, जो उनकी फसलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने गोबर की खाद का भी उपयोग किया, जिससे मिट्टी की उर्वका में वृद्धि हुई है। पहले अधिक पानी की समस्या के कारण सब्जियों की फसलें खराब हो जाती थीं। अब ड्रिप लाइन सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पानी की बचत हो रही है और फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस प्रणाली की स्थापना में पंजाब सरकार ने उन्हें सब्सिडी और अन्य सहायता प्रदान की है, जिससे गर्मी के मौसम में भी फसलों की उत्पादकता में इजाफा हुआ है।

जैविक खेती की शुरूआत में उन्हें काफी खर्च और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनके प्रयास रंग ला रहे हैं। उन्होंने किसानों को वैकल्पिक खेती अपनाने और जैविक विधियों की ओर झुकान बढ़ाने की सलाह दी। उनका यह भी मानना है कि कृषि के क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों को अपनाना न केवल किसानों के लिए वरदान है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा व पर्यावरण के लिए भी लाभकारी साबित हो सकता है।

इण्डोफिल का वायदा सेहतमंद आलू और बढ़िया पैदावार



इण्डोफिल
इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड